



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264141
CG-DL-E-25062025-264141

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2792]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2025/आषाढ़ 4, 1947

No. 2792]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2025/ASHADHA 4, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2025

(आयकर)

का.आ. 2858(अ).— चूंकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारतीय गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच करार को संशोधित करने वाले एक प्रोटोकॉल पर दिनांक 27 जनवरी, 2025 को मस्कट में हस्ताक्षर किए गए थे, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रोटोकॉल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में निर्धारित किया गया है;

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल दिनांक 28 मई, 2025 को लागू हुआ, जो कि अनुच्छेद 15 के पैरा 2 के अनुसार, उक्त प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए संविदाकारी राज्यों के संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख है;

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 के पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (क) में यह प्रावधान किया गया है कि इस करार के प्रावधान भारत में इसके बाद प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख के बाद अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में लागू होंगे;

अतः अब, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 90 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त करार और प्रोटोकॉल के सभी प्रावधान, जैसा कि इसके साथ संलग्न है, भारत संघ में लागू होंगे।

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए
 भारत गणराज्य की सरकार
 और
 ओमान सल्तनत की सरकार
 के बीच करार में संशोधन प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार,

दोहरे कराधान के परिहार और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए 2 अप्रैल 1997 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित भारत गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच करार को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल संपन्न करने की इच्छा रखते हुए (जिसे आगे "करार" कहा जाएगा)।

निम्नानुसार सहमति हुई है:

अनुच्छेद 1

करार की प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

"भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार,
 आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए एक करार करने की इच्छा रखते हुए;

कर अपवंचन या परिहार के माध्यम से गैर-कर या कम कराधान के अवसर पैदा किए बिना इस करार द्वारा शामिल किए गए करों के संबंध में दोहरे कराधान को खत्म करने का इरादा रखते हुए (तीसरे राज्यों के निवासियों के अप्रत्यक्ष लाभ के लिए इस करार में प्रदान की गई राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी व्यवस्था के माध्यम से);

निम्नानुसार सहमति हुई है:"

अनुच्छेद 2

करार के अनुच्छेद 2 (आच्छादित कर) के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"ओमान सल्तनत में : आयकर;

(इसके बाद इसे "ओमानी कर" कहा जाएगा);"

अनुच्छेद 3

1. करार के अनुच्छेद 3 (सामान्य परिभाषाएँ) के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ड.) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"भारत के मामले में "सक्षम प्राधिकारी" शब्द का तात्पर्य भारत सरकार के वित्त मंत्री या उनके अधिकृत प्रतिनिधि से है; और ओमान सल्तनत के मामले में कर प्राधिकरण के अध्यक्ष या उनके अधिकृत प्रतिनिधि से है।"

2. करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (छ) (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"ओमान सल्तनत के मामले में, 'कर वर्ष' जैसा कि उसके आयकर कानून में परिभाषित किया गया है;"

अनुच्छेद 4

करार के अनुच्छेद 4 (व्यष्टि) के पैराग्राफ 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"जहां किसी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का व्यष्टि है, वहां संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी आपसी सहमति से यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि इस करार के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को किस संविदाकारी राज्य का व्यष्टि माना जाएगा, जिसमें उसके प्रभावी प्रबंधन का स्थान, वह स्थान जहां वह निगमित है या अन्यथा गठित है और कोई अन्य प्रासंगिक कारक शामिल हैं। ऐसे करार के अभाव में, ऐसा व्यक्ति इस करार द्वारा प्रदान की गई किसी भी राहत या कर छूट का हकदार नहीं होगा, सिवाय उस सीमा तक और ऐसे तरीके से जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है।"

अनुच्छेद 5

करार के अनुच्छेद 8 (वायु परिवहन) के पैराग्राफ 5 को हटा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 6

1. अनुच्छेद 10 (संबद्ध उद्यम) का मौजूदा पाठ पैराग्राफ 1 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा।

2. अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 1 के बाद पैराग्राफ 2 के रूप में निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा:

"2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभ में शामिल करता है - और तदनुसार कर लगाता है - ऐसे लाभ जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार शामिल किए गए लाभ वे लाभ हैं जो पहले उल्लेखित राज्य के उद्यम को प्राप्त होते यदि दो उद्यमों के खच की शर्तें वही होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के खच होतीं, तो वह दूसरा राज्य उन मुनाफ़ों पर लगाए गए कर की राशि में उचित समायोजन करेगा। ऐसे समायोजन का निर्धारण करते समय, इस करार के अन्य प्रावधानों पर उचित ध्यान दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी एक दूसरे से परामर्श करेंगे।"

अनुच्छेद 7

करार के अनुच्छेद 13 (रॉयल्टी) के पैराग्राफ 2 में, '15 प्रतिशत' शब्द को 'दस प्रतिशत (10%)' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुच्छेद 8

करार के अनुच्छेद 14 (तकनीकी शुल्क) के पैराग्राफ 2 में, '15 प्रतिशत' शब्द को 'दस प्रतिशत (10%)' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुच्छेद 9

1. करार के अनुच्छेद 25 (दोहरे कराधान से बचाव) के पैराग्राफ 4 को हटा दिया जाएगा।

2. करार के अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 5 को पैराग्राफ 4 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

अनुच्छेद 10

अनुच्छेद 25 के बाद निम्नलिखित नया अनुच्छेद 25 का जोड़ा जाएगा:

"अनुच्छेद 25 का

गैर-भेदभाव

1. किसी संविदाकारी राज्य के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी ऐसे कराधान अथवा उससे जुड़ी किसी आवश्यकता के अधीन नहीं रखा जाएगा, जो उस कराधान और उससे जुड़ी आवश्यकताओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल हो, जिसके अधीन उस दूसरे राज्य के नागरिक समान परिस्थितियों में, विशेष रूप से निवास के संबंध में, हैं।

अथवा हो सकते हैं। यह प्रावधान, अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थापित स्थायी प्रतिष्ठान पर लगाया जाने वाला कराधान, उसी राज्य में उसी प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने वाले दूसरे राज्य के उद्यमों पर लगाए जाने वाले कराधान से कम अनुकूल नहीं होगा। इस प्रावधान को किसी संविदाकारी राज्य द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को नागरिक स्थिति अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कराधान के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्तिगत भत्ता, राहत और कटौतियां प्रदान करने के लिए बाध्य करने के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता है। इस प्रावधान को किसी संविदाकारी राज्य को पहले उल्लिखित राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कंपनी द्वारा स्थापित स्थायी प्रतिष्ठान के मुनाफे पर कर की ऐसी दर से अधिक कर लगाने से रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो पहले उल्लिखित संविदाकारी राज्य की किसी समान कंपनी के मुनाफे पर लगाए जाने वाले कर की दर से अधिक है, न ही इसे अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के प्रावधानों के साथ संघर्ष में माना जाएगा।
3. सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7, अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 6 और अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 6 के प्रावधान लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को दिए गए व्याज, रॉयलटी, तकनीकी शुल्क और अन्य संवितरण, ऐसे उद्यम के कर योग्य लाभ का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे जैसे कि वे पहले उल्लिखित राज्य के निवासी को भुगतान किए गए हों।
4. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम, जिनकी पूँजी पूर्णतः अथवा अंशतः, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा अधिक निवासियों के स्वामित्व में अथवा उनके नियंत्रण में है, प्रथम वर्णित संविदाकारी राज्य में किसी ऐसे कराधान अथवा उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं होंगे जो उन कराधान और संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल हो जिनके अधीन प्रथम वर्णित राज्य के अन्य समान उद्यम हैं अथवा हो सकते हैं।
5. इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल उन करों पर ही लागू होंगे जो इस करार के अंतर्गत आते हैं।

अनुच्छेद 11

करार के अनुच्छेद 26 (पारस्परिक करार प्रक्रिया) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

1. जहां कोई व्यक्ति यह मानता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उस पर इस करार के प्रावधानों के अनुसार कराधान नहीं होगा, तो वह उन राज्यों के घरेलू कानून द्वारा प्रदान किए गए उपायों पर ध्यान दिए बिना, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है अथवा, यदि उसका मामला अनुच्छेद 25क के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है, तो उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, जिसका वह नागरिक है। मामले को करार के प्रावधानों के अनुसार कराधान नहीं होने के परिणामस्वरूप कार्रवाई की पहली अधिसूचना से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित प्रतीत होती है और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक समाधान पर पहुँचने में सक्षम नहीं है, तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ आपसी सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेगा, ताकि करार के अनुसार न होने वाले कराधान से बचा जा सके। किसी भी करार पर पहुँचने पर उसे संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानून में किसी भी समय सीमा के बावजूद लागू किया जाएगा।
3. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी करार की व्याख्या अथवा उसके अनुपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई अथवा संदेह को आपसी सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे करार में प्रावधान न किए गए मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए भी आपस में परामर्श कर सकते हैं।
4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के अर्थ में किसी करार पर पहुँचने के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं।

अनुच्छेद 12

करार के अनुच्छेद 27 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी जानकारी (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के प्रावधानों अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनीतिक उपविभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए हर प्रकार और विवरण के करों से संबंधित घरेलू कानूनों के कार्यान्वयन के लिए पूर्वानुमानित रूप से प्रासंगिक है, जब तक कि इसके तहत कराधान करार के विपरीत न हो। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जैसे उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना को गुप्त माना जाता है और इसका खुलासा केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकायों सहित) के समक्ष किया जाएगा जो अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट करों के संबंध में निर्धारण अथवा संग्रह, प्रवर्तन अथवा अभियोजन, अपीलों के निर्धारण अथवा उपर्युक्त की निगरानी से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए करेंगे। वे सार्वजनिक अदालती कार्यवाही में अथवा न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं। पूर्वगामी होने के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है यदि ऐसी सूचना का उपयोग दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता हो और आपूर्ति करने वाले राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे उपयोग को अधिकृत करता हो।
3. किसी भी मामले में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व थोरें:
 - क. उस अथवा अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;
 - ख. ऐसी जानकारी (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) प्रदान करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त नहीं की जा सकती है;
 - ग. ऐसी सूचना प्रदान करना जो किसी व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक रहस्य अथवा व्यापार प्रक्रिया का खुलासा करती हो, अथवा ऐसी सूचना जिसका खुलासा सार्वजनिक नीति (सार्वजनिक नीति) के विपरीत हो।
4. यदि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य द्वारा सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्रित करने के उपायों का उपयोग करगा, भले ही उस दूसरे राज्य को अपने कर उद्देश्यों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, लेकिन किसी भी मामले में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि कोई संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना कर सकता है क्योंकि उसका ऐसी सूचना में कोई घरेलू हित नहीं है।
5. किसी भी मामले में अनुच्छेद 3 के प्रावधानों की यह व्याख्या नहीं की जाएगी कि यह संविदाकारी राज्य को सूचना देने से केवल इसलिए इंकार करने की अनुमति देता है क्योंकि वह सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, नामित व्यक्ति अथवा एजेंसी अथवा न्यासीय क्षमता में कार्यरत व्यक्ति के पास है अथवा क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वामित्व हितों से संबंधित है।"

अनुच्छेद 13

करार के अनुच्छेद 27 के तुरंत बाद निम्नलिखित नए अनुच्छेद 27क और 27ख सम्मिलित किए जाएंगे:

"अनुच्छेद 27क

करों के संग्रह में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों के संग्रह में एक-दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस अनुच्छेद के लागू होने के तरीके को तय कर सकते हैं।
2. इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का अर्थ है संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनीतिक उपविभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार और वर्णित करों के संबंध में बकाया राशि, जहां तक उसके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा किसी अन्य दस्तावेज के प्रतिकूल न हो, जिसके संविदाकारी राज्य पक्षकार हों, साथ ही ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक दंड और संग्रहण अथवा संरक्षण की लागत।
3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय हो और उस पर किसी ऐसे व्यक्ति का बकाया हो जो उस समय उस राज्य के कानूनों के तहत उसके संग्रह को रोक नहीं सकता, तो उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संग्रह के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस दूसरे राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और संग्रह पर लागू अपने कानूनों के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाएगा जैसे कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा हो।
4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा ऐसा दावा है जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानून के तहत उसके संग्रह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय कर सकता है, तो उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। वह दूसरा राज्य अपने कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उस राजस्व दावे के संबंध में संरक्षण के उपाय करेगा जैसे कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा हो, भले ही ऐसे उपायों को लागू करने के समय राजस्व दावा पहले उल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय न हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बकाया हो जिसे उसके संग्रह को रोकने का अधिकार है।
5. पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के बावजूद, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनों के लिए किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा, उस राज्य में, उस राज्य के कानूनों के तहत राजस्व दावे के लिए लागू समय सीमा के अधीन नहीं होगा अथवा उसे कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनों के लिए किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा, उस राज्य में, दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत उस राजस्व दावे के लिए लागू कोई प्राथमिकता नहीं रखेगा।
6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष ही लाई जाएगी। इस अनुच्छेद में किसी भी बात को दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही करने का किसी अधिकार का सृजन करने अथवा अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं समझा जाएगा।
7. जहां, किसी भी समय अनुच्छेद 3 अथवा 4 के अंतर्गत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् तथा दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को एकत्रित करके प्रथम वर्णित राज्य को प्रेषित किए जाने से पूर्व, संबंधित राजस्व दावा समाप्त हो जाता है।
 - क. अनुच्छेद 3 के तहत अनुरोध के मामले में, पहले उल्लिखित राज्य का राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और उस व्यक्ति द्वारा बकाया है, जो उस समय, उस राज्य के कानूनों के तहत, उसके संग्रह को रोक नहीं सकता है, अथवा
 - ख. अनुच्छेद 4 के अधीन अनुरोध के मामले में, प्रथम उल्लिखित राज्य का राजस्व दावा जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के अधीन, उसके संग्रह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय कर सकता है, प्रथम उल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी तुरंत उस तथ्य के बारे में दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर, प्रथम उल्लिखित राज्य उसके अनुरोध को अथवा तो निलंबित कर देगा अथवा वापस ले लेगा।
8. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि वे किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व थोपें:
 - क. उस अथवा अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;

- ख. ऐसे उपाय करना जो सार्वजनिक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;
- ग. यदि अन्य संविदाकारी राज्य ने अपने कानूनों अथवा प्रशासनिक पद्धति के तहत उपलब्ध संग्रहण अथवा संरक्षण के सभी उचित उपायों को नहीं अपनाया है, तो सहायता प्रदान करना;
- घ. उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहाँ उस राज्य का प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से असंगत है।

अनुच्छेद 27वाँ

लाभ की पात्रता

इस करार के अन्य प्रावधानों के बावजूद, इस करार के तहत किसी आय मद के संबंध में लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा यदि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि उस लाभ को प्राप्त करना किसी भी व्यवस्था अथवा लेनदेन का प्रमुख उद्देश्य था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वह लाभ प्राप्त हुआ, जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि इन परिस्थितियों में उस लाभ को प्रदान करना इस करार के प्रासंगिक प्रावधानों के उद्देश्य और प्रयोजन के अनुसार होगा।"

अनुच्छेद 14

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच 2 अप्रैल 1997 को हस्ताक्षर हुए करार के प्रोटोकॉल को, हटा दिया जाएगा।

अनुच्छेद 15

1. संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे को इस प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की लिखित सूचना देंगे।
2. यह प्रोटोकॉल इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख से लागू होगा।
3. इसके बाद प्रोटोकॉल के प्रावधान लागू होंगे:

क. भारत में

प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख के बाद अप्रैल के पहले दिन अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में।

ख. ओमान सल्तनत में

प्रोटोकॉल लागू होने की तारीख के बाद किसी भी कर वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में।

4. यह प्रोटोकॉल तब तक लागू रहेगा जब तक यह करार लागू रहेगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप नीचे हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत होकर इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक 27 जनवरी, 2025 को मस्कट में हिंदी, अंग्रेजी और अरबी भाषाओं में 27 रजब 1446 हिजरी को दो प्रतियों में हस्ताक्षरित किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इन पाठों की भिन्न व्याख्या के मामले में, अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए
ओमान सल्तनत में भारतीय गणराज्य के
दूतावास के राजदूत

ओमान सल्तनत की सरकार के लिए
कर प्राधिकरण के अध्यक्ष

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2025

(INCOME-TAX)

S.O. 2858(E).— Whereas, a Protocol amending the Agreement between the Republic of India and the Sultanate of Oman for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, was signed at Muscat on the 27th day of January, 2025, as set out in the Annexure to this notification (hereinafter referred to as the Protocol);

And whereas, the said Protocol entered into force on the 28th day of May, 2025, being the date of receipt of the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws of the Contracting States for entry into force of the said Protocol, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of the said Protocol;

And whereas, sub-paragraph (a) of paragraph 3 of Article 15 of the said Protocol provides that the provisions of the Agreement shall thereupon have effect in India in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the date on which the Protocol enters into force.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Agreement and Protocol, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE**PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE****GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA****AND****THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN****FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the Sultanate of Oman,

Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Republic of India and the Sultanate of Oman for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at New Delhi on 2 April 1997 (hereinafter referred to as "the Agreement").

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Preamble of the Agreement shall be replaced by the following:

"The Government of the Republic of India and the Government of the Sultanate of Oman,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income;

Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this Agreement without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this agreement for the indirect benefit of residents of third States);

Have agreed as follows:"

ARTICLE 2

Sub-paragraph (b) of paragraph 1 of Article 2 (Taxes Covered) of the Agreement shall be replaced by the following:
 "in the Sultanate of Oman: the income tax;
 (hereinafter referred to as "Omani tax")

ARTICLE 3

1. Sub-paragraph (e) of paragraph 1 of Article 3 (General Definitions) of the Agreement shall be replaced by the following:

"The term "competent authority" means in the case of India, the Finance Minister, Government of India or his authorised representative; and in the case of the Sultanate of Oman, the Chairman of Tax Authority or their authorised representative."

2. Sub-paragraph (g) (ii) of paragraph 1 of Article 3 of the Agreement shall be replaced by the following:

" in the case of the Sultanate of Oman, 'tax year' as defined in its income tax law;"

ARTICLE 4

Paragraph 3 of Article 4 (Resident) of the Agreement shall be replaced by the following:

"Where a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption of tax provided by this Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States."

ARTICLE 5

Paragraph 5 of Article 8 (Air Transport) of the Agreement shall be deleted

ARTICLE 6

1. The existing text of Article 10 (Associated Enterprise) shall be numbered as paragraph 1.
2. The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 of Article 10 as paragraph 2:

"2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other."

ARTICLE 7

In paragraph 2 of Article 13 (Royalties) of the Agreement, the term '15 per cent' shall be replaced by 'ten per cent (10%)'.

ARTICLE 8

In paragraph 2 of Article 14 (Technical Fees) of the Agreement, the term '15 per cent' shall be replaced by 'ten per cent (10%)'.

ARTICLE 9

1. Paragraph 4 of Article 25 (Avoidance of Double Taxation) of the Agreement shall be deleted.
2. Paragraph 5 of Article 25 of the Agreement shall be re-numbered as paragraph 4.

ARTICLE 10

The following new Article 25A shall be inserted after Article 25:

"Article 25A

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 10, paragraph 7 of Article 12, paragraph 6 of Article 13 and paragraph 6 of Article 14, apply, interest, royalties, technical fees and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and

connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall apply only to taxes which are covered by this Agreement.

ARTICLE 11

Article 26 (Mutual Agreement Procedure) of the Agreement shall be replaced by the following:

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provision of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25A, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs."

ARTICLE 12

Article 27 of the Agreement shall be replaced by the following:

"Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - a. to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b. to supply information (including documents or certified copies of the documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - c. to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).
4. If the information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in person."

ARTICLE 13

The following new Articles 27A and 27B shall be inserted immediately after Article 27 of the Agreement:

"Article 27A

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.
2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.
4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first- mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.
6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State.
7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be
 - a. in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first- mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or
 - b. in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first- mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.
8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - a. to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b. to carry out measures which would be contrary to public policy (*ordre public*);
 - c. to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
 - d. to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Article 27B

ENTITLEMENT TO BENEFITS

Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement.”

ARTICLE 14

The Protocol to the Agreement between the Republic of India and the Sultanate of Oman for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed on 2 April 1997, shall be deleted.

ARTICLE 15

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Protocol.
2. This Protocol shall enter into force on the date of the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.
3. The provisions of the Protocol shall thereupon have effect:
 - a. in India
in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the date on which the Protocol enters into force.
 - b. in the Sultanate of Oman
in respect of income derived in any tax year following the date on which the Protocol enters into force.
4. This Protocol shall remain in effect as long as the Agreement remains in force.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Muscat on this 27th day of January, 2025 corresponding to the 27 Rajab 1446 AH in the Hindi, English and Arabic languages, all the texts being equally authentic. In case of divergent interpretation of the texts, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDIA**

Ambassador of the Republic of India
to the Sultanate of Oman

**FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE
OF OMAN**

Chairman of the Tax Authority

[Notification No. 69/2025/F. No. 501/6/1991-FTD-II]

ANCHAL KHANDELWAL, Director